

U.N. Survey on slaves in India

578. SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware about the fact that according to a U.N. Survey, India has the distinction of having 5 million slaves; and

(b) if so, what is Government's reaction in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) The U.N. have not conducted any such survey.

(b) Does not arise.

क्षेत्रीय श्रम-आयुक्त द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

579. श्री हुसमदेव नारायण यादव: क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में क्षेत्रीय श्रम-आयुक्त द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और उनमें से कितने मामलों में प्रतिष्ठानों को दोषी पाया गया तथा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कानून की कार्यवाही की गई ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई): विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन निरीक्षण श्रम प्रवर्तन अधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा किए जाते हैं। वर्ष 1979 (क्षेत्रीय) द्वारा किए जाते हैं। वर्ष 1979 से 1981 के दौरान प्रवर्तन अधिकारियों अर्थात् सम्बन्धित श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (क्षेत्रीय) और गहायता श्रमायुक्तों (क्षेत्रीय) ने बिहार में 8,888 निरीक्षण किए जिनके परिणामस्वरूप 45,698 अनियमितताओं का पता लगाया गया और 1225 अभियोग दायर किए गये। क्षेत्रीय श्रमायुक्त (क्षेत्रीय) धनबाद ने भी ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम के अधीन अगस्त 1981 में दो प्रतिष्ठानों के बारे में स्वयं जांच निरीक्षण किए ताकि उनको कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहले किये गये

निरीक्षणों का जांच निरीक्षण किया जा सके।

गंगा पुल के कर्मचारों को मूआवजे का भुगतान

580. श्री हुसमदेव नारायण यादव: क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेमन इन्डिया लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन गंगा पुल में किस प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने काम पर लगाये गए थे और सभी कितने लोग वहाँ काम पर हैं;

(ख) कितने लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें घायल हुए कितने और घायल काम के लायक नहीं रहे;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति को कितने मूआवजे का भुगतान किया गया; और

(घ) क्या उक्त कम्पनी द्वारा श्रम कानून लागू किये गए हैं; यदि हाँ, तो मजदूरों का कितना वकाला किस मद में कम्पनी के जिम्मे भुगतान हेतु कब से लम्बित है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई): (क) में (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभी की सज पर रख दी जाएगी।

Labourers engaged by Central and State Governments for construction work

581. SHRI G. C. BHATTACHARYA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a new item published in the Hindustan Times dated the 21st August, 1982 to the effect that the Rajasthan Bhil labourers as also other construction labourers engaged in construction work of Central Government and the Central Government and the State Governments are living under abject conditions; and

(b) whether Government will provide minimum and bare amenities and shelter to these labourers and set example as an ideal employer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) On the news item relating to Rajasthani Bhil labourers Teferred to, Delhi Development Authority have reported that a number of bhil families are living in an area known as Bhil Basti in Baljit Nagar near West Patel Nagar which is a notified slum and that basic amenities like drinking water, electricity and footpaths in the colony have been provided.

(b) The Delhi Development Authority have further reported that their Slum Department is proposing to carry out a socio-economic survey of Baljit. Nagar to ascertain the extent of the problems and their appropriate golution by providing some of the basic amenities of life and by improving the environments subject to availability of funds during the next financial year.

Textile workers strike in Bonibay

582. SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

- (a) whether trade union leaders have held any tal
- (b) whether it is a fact that the strike was called by a non-recognised union; and
- (c) if so, what action Government propose to take to stop the non-recognised union giving call for the strike?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINTSTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. The strike has been called by an un-recognised union.

(c) An illegal strike, an unfair labour practice under the Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971 is an offence punishable under the Act.

न्यूनतम मजदूरी के संबंध में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के निर्देश

583. श्री राम भगत पासवान : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में व्यापार क्या है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) :

(क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधिन, संबंधित सरकार अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित राजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए सक्षम है। जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन ने सिफारिश की कि संबंधित सरकारों का यह प्रयास होना चाहिए कि वे समय-समय पर अनुसूची में यथा- संभव अधिक राजगारों को शामिल करके कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करें। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि न्यूनतम मजदूरी दरों को, यदि आवश्यक हो, कम से कम, दो वर्ष में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 पाइंटो की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, पुनरीक्षा की जानी चाहिए और उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। इस सिफारिश को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया।

xtile workers strike Jn Boml

Payment to National Herald Employees

584. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the Provident Fund and E.S.I. re-imbusement have not been paid to the employees of National Herald and yet they are starting new editions of the paper from other State capitals; and